



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235]  
No. 235]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 1978/अग्रहायण 24, 1900  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 1978/AGRAHAYANA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1978

संकल्प

सं० 156(9)/77 पालिसी-1.—भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 156(9)/74-पालिसी-1 में एक सलाहकार परिषद् स्थापित की गयी थी। इस परिषद् की बैठक की खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रकट करने के लिए एक फोरम बनाने का हरादा था और जिसके माध्यम से भारत सरकार अपनी खाद्य नीति को कार्यान्वित करने में उत्पादकों, उपभोक्ताओं, सहकारी समितियों, खाद्यान्न व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों की सलाह और उनका सहयोग प्राप्त कर सके। इस संकल्प में यह स्पष्ट किया गया था कि यह सलाहकार परिषद् दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी। 10 दिसम्बर, 1975 को गठित इस सलाहकार परिषद् का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है, भारत सरकार ने एक नई सलाहकार परिषद् गठित करने का निश्चय किया है जिसके निम्नलिखित विचारार्थ विषय होंगे:—

- (1) सरकार को खाद्य नीति—अधिप्राप्ति, वितरण, मूल्य आदि के बनाने में परामर्श देना।

- (2) सरकार को खाद्य नीति के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापारियों तथा विद्यमान उद्योग का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना।

- (3) खाद्य नीति की कार्यान्वित सम्बन्धी विशिष्ट समस्याओं पर विचार-विमर्श करना जैसे कि—

- (क) मूल्य में स्थिरता बनाए रखने में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की अपनी अपनी भूमिकाएं;
- (ख) बाजार अपूर्णता जैसे कि मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय अन्तर को समाप्त करने के उपायों की समीक्षा करना;
- (ग) अनाज संचालन की कार्यकुशलता सुधारने के तरीके सुझाना जिससे उसकी किस्म सुधारी जा सके और पश्चालन व्यय कम किया जा सके।

- (4) नीति के बारे में नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सरकार को परामर्श देना।

- (5) भण्डारण, विपणन और विधायन उद्योगों तथा पोषाहार सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास की योजनाओं से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यक्रमों पर सरकार को परामर्श देना।

2. सलाहकार परिषद् दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी।

3. सलाहकार परिषद की सदस्यता निम्न प्रकार होगी :—

- |   |            |
|---|------------|
| 1. केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री          | अध्यक्ष    |
| 2. कृषि और सिंचाई राज्य मंत्री              | उपाध्यक्ष  |
| 3. उपाध्यक्ष, योजना आयोग                    | सदस्य      |
| 4. वित्त राज्य मंत्री                       |            |
| 5. नागरिक पूर्ति और सहकारिता राज्य मंत्री   |            |
| 6. सचिव, खाद्य विभाग                        |            |
| 7. सचिव, कृषि विभाग                         |            |
| 8. सचिव, योजना आयोग                         |            |
| 9. सचिव, नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग    |            |
| 10. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम              |            |
| 11. अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग                |            |
| 12. अपर सचिव, खाद्य विभाग                   |            |
| 13. संयुक्त सचिव (प्रशासन), खाद्य विभाग     | सदस्य-सचिव |
| 14. संयुक्त सचिव (वित्त), खाद्य विभाग       |            |
| 15. संयुक्त सचिव (निर्माण), खाद्य विभाग     |            |
| 16. संयुक्त सचिव (डी०एण्ड आर०), खाद्य विभाग |            |

#### गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री सतीश बागड़ी, संसद सदस्य
2. श्री लक्ष्मी नारायण नायक, संसद सदस्य
3. श्री के०एच० रामास्वामी, संसद सदस्य
4. श्री एम०आर० कृष्णा, संसद सदस्य
5. डा० वी०एल० शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ।
6. उप कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर
7. डा० राम दास, एम०ए०, पी०एच०डी०, ए-28, फ्रेंच कालोनी, नई दिल्ली ।
8. डा० वी० रामलिंगास्वामी, निदेशक, अखिल भारतीय आर्युर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
9. श्री हरबंस सिंह, प्रबन्ध निदेशक, एच०पी०एस०सी०, शिमला ।
10. श्री कैलाशनाथ, मैनेजिंग प्रोप्राइटर, मै० हरनारायण गोपीनाथ, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।
11. श्री के०बी० त्यागराजन, सचिव, अखिल भारतीय रोस्टर-पब्लिशर्स मिस्ट एसोसिएशन, नई दिल्ली ।
12. श्री रेवती रमण, सचिव, खाद्य मिस्ट एसोसिएशन, रुद्रपुर ।
13. श्री श्रीपाल सिंह, अध्यक्ष यू०पी० कोऑपरेटिव फीडरेशन लि०, 6 कैप्ट रोड, लखनऊ ।
14. श्री भाना राम गुप्त, अध्यक्ष, अखिल भारतीय खाद्य व्यापारी संघ, 3979, नया बाजार, दिल्ली ।
15. श्री देवेन्द्र सिंह, द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
16. श्री अतहर अहमद, ग्राम पोखर भेतवा, डाकघर तेलरी बाजार, जिला बस्ती ।
17. श्री मुत्तुलक्ष, पोलिथेक्कम 603309, चिन्नलपेट, जिला (तमिलनाडु)
18. श्री बलवीर मिश्र बीधरी, पी० आ० फतेहाबाद, 125050, जिला हिसार ।
19. श्री ए०पी० रत्नोनी, प्रभात फार्म, खेतमा-262308, जिला नैनीताल ।
20. श्री ए०के० गणपथाय्या, हारले इस्टेट, मकलेसपुर, पोस्ट जिला हसन (कर्नाटक) ।

21. श्री रमणभाई पटेल, एम०एल०ए०, सनहुज 387430, जिला कैरा (गुजरात) ।

22. श्री राम देव प्रसाद, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, बिहार शाखा, पटना ।

23. श्री यादवेन्द्र सिंह, ग्राम पञ्चके जिला संगरूर ।

24. श्री एन०पी० गुप्त, सचिव, टैक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, भद्रमदाबाद

25. श्रीमती पी० बंडवते, 8, कृष्णामनन मार्ग, नई दिल्ली ।

4. प्राप्ता है कि परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी ।

आर० बालसुब्रह्मण्यन, सचिव

#### MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

New Delhi, the 15th December, 1978

#### RESOLUTION

No. 156(9)/77 -Py. I.—In Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) Resolution No. 156(9)/74-PY. I dated the 10th September, 1973, an Advisory Council was set up which was intended to be a forum to reflect the various points of view on Food and Agricultural problems facing the country, and through which the Government of India could secure the advice and cooperation of producers, consumers, cooperatives, foodgrains trade and economists in the implementation of the Food Policy. In this Resolution, it was specified that the Advisory Council would function for a period of two years. Now that the period of functioning of the Advisory Council constituted on 10th September, 1974 has expired, the Government of India have decided to constitute a new Advisory Council with the following terms of reference:—

- (1) To advise Government in formulation of food policy—procurement, distribution, prices etc.
- (2) To advise Government on measures to be adopted to secure maximum cooperation of trade and processing industry in fulfilling the national objectives of food policy.
- (3) To discuss specific problems of implementation of food policy such as—
  - (a) respective roles of public and private agencies in maintaining price stability ;
  - (b) to review measures to remove market imperfections such as inter-State disparities in prices.
  - (c) to suggest methods to improve efficiency of handling grain both to improve quality and reduce operational costs.
- (4) To advise Government in formulation and implementation of policy regarding sugar.
- (5) To advise Government on specific programmes relating to plans for development of storage, marketing and processing industries and nutrition programmes.

2. The Advisory Council shall function for a period of two years.

3. The membership of the Advisory Council shall be as follows :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Union Minister of Agriculture & Irrigation                       | Chairman      |
| 2. Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation. | Vice-Chairman |

- R. BALASUBRAMANIAN, Secretary.

